Indian J. Soc. & Pol. 09 (02) : 113-116: 2022 **ISSN : 2348-0084 (PRINT)**
First Published Online 31 JULY 2022 **ISSN: 2455-2127(ONLINE)**

उत्तर प्रदेश विधान सभा चुनाव 2022 : जातिगत वर्चस्व का टूटता तिलस्म एवं वर्गीय राजनीति की जीत

संजय कुमार[1]

[1]एसो. प्रोफेसर, युवराज दत्त महाविद्यालय, लखीमपुर खीरी, – राज्य समन्वयक, सी.एस.एस.पी, कानपुर, उ0प्र0, भारत

ABSTRACT

1991 में भारत में आर्थिक उदारीकरण का दौर प्रारंभ हुआ. साथ हीं मंडल और कमंडल का दौर भी. तीस वर्षों के पश्चात् ऐसा लगता है कि राजनीति का एक चक्र भी पूरा हो गया है. जिसकी झलक 2022 के विधानसभा चुनाव के निर्णय से स्पष्ट हो जाता है. क्योंकि पिछले तीस वर्षों का रिकॉर्ड उत्तर प्रदेश में टूट गया है. 1991 में विधानसभा चुनाव के पश्चात बहुमत के साथ भाजपा के पहले मुख्यमंत्री के तौर पर कल्याण सिंह ने 24 जून को शपथ ली थी. उसके बाद 1993, 1996, 2002, 2007, 2012, 2017 एवं 2022 में यानी कुल आठ विधानसभा का चुनाव हुआ, परन्तु कोई भी दल दुबारा सता में वापसी नहीं कर पाई. 2022 के चुनाव में योगी आदित्यनाथ ने न सिर्फ इस मिथक को तोड़ा, वरन पूरे बहुमत के साथ सत्ता में वापसी की, जबकि परिस्थितियाँ इनके प्रतिकूल थी. तो क्या चुनाव परिणाम को एक तुक्का मान लिया जाय अथवा उत्तर प्रदेश में जो मूलभूत राजनीतिक परिवर्तन हुए हैं, उसे समझने में बाकी अन्य दल पीछे रह गए? क्या उत्तर प्रदेश एक लम्बे दलीय स्थायित्व के दौर में प्रवेश कर गया है अथवा अभी कुछ होना बाकी रह गया है?

KEYWORDS: *लोकतंत्र, निर्वाचन, विधान सभा, उ0प्र0, जाति, वर्ग*

निर्विवाद रूप से पहला (1951–1967) और दूसरा चरण (1967–1989) कांग्रेस काल है, परन्तु 1967 चुनाव के साथ कांग्रेस में दरारें भी दिखनी शुरू हो गयी थीं जिसका स्पष्ट लक्षण 1989 के पश्चात् दिखने लगा और लगातार कांग्रेस कमजोर होते हुए आज सिर्फ 2 सीटों पर सिमट चुकी है. वोट प्रतिशत के हिसाब से भी लगभग सवा दो प्रतिशत पर सिमट चुकी है. पिछले 33 वर्षों से यह सत्ता से बहुत बहुत दूर हो चुकी है और निकट भविष्य में इसके पुनरुद्धार की सम्भावना भी काफी कम लगती है. सारिणी संख्या 1 से यह बात स्पष्ट हो जाती है.

सारणी संख्या 2 से यह बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है कि भाजपा निर्विवाद रूप से आज सबसे बड़े दल के तौर पूरे देश के साथ उत्तर प्रदेश में भी स्थापित हो गया है, तथा अब राजनीतिक प्रतिद्वंदिता के केंद्र बिंदु के रूप में भाजपा बनाम अन्य दल हो चुका है. दरअसल 2022 के चुनाव ने भारत के साथ साथ उत्तर प्रदेश के राजनीतिक चरित्र में एक मूलभूत परिवर्तन कर दिया है. मतदाता अपना वोट देते समय भाजपा बनाम अन्य के विकल्प के हिसाब से अब सोचने लगा है. 'कांग्रेस का विकल्प' अथवा 'कांग्रेस के लिए' मतदान उत्तर प्रदेश की राजनीति से लगभग गायब हो चुका है. सिर्फ 2.36 प्रतिशत मत प्राप्त करना पूरे तस्वीर की कहानी बता दे रहा है. यहाँ तक कि अपना दल, निषाद पार्टी, सुभासपा और रालोद जैसी क्षेत्रीय दलों के मुकाबले भी कांग्रेस का प्रदर्शन खराब रहा. 2007 में अपने दम पर बहुमत से सरकार बनाने वाली बसपा भी अपने निम्नतम स्तर पर पहुँच चुकी है और इसके भविष्य को लेकर सवाल खड़े होने लगे हैं. कहा तो यह भी जाता है कि इस चुनाव में बसपा ने भाजपा की 'बी' टीम बनकर चुनाव लड़ा और सपा को हराने में तथा भाजपा को जिताने में मदद की. सिर्फ 12.88 प्रतिशत वोट और एक सीट प्राप्त करना एक बड़ा सवाल तो खड़ा कर हीं रहा है. तमाम राजनीतिक चर्चाओं में सबसे प्रमुख चर्चा यह भी रही कि बसपा चुनाव हारने के लिए सारे जतन करती हुई नजर आई.

सवाल अब यह उठता है कि ऐसा क्यों हो रहा है? क्या उत्तर प्रदेश की राजनीति से जातीय वर्चस्वता एवं अस्मिता का दौर खत्म हो रहा है और उसकी जगह वर्गीय चेतना का एक नया दौर प्रारंभ हो रहा है? नब्बे के दशक से जातीय राजनीति का जो दौर प्रारंभ हुआ था, क्या वह समाप्त हो गया है अथवा उस पर केवल एक अस्थायी विराम लगा है? यह तो भविष्य हीं बताएगा. परन्तु जिस तेजी के साथ राजनीतिक परिस्थितियां बदल रही हैं उससे एक दीर्घकालिक मतदाता रूझान की स्थिति स्पष्ट हो रही है. इस रूझान के कुछ ठोस कारण तो साफ साफ दिख रहे हैं और कुछ तरल कारण भी दिख रहे हैं.

ठोस कारण –

1. **योगी आदित्यनाथ की प्रशासनिक क्षमता :** कोरोना काल में प्रवासी मजदूरों के पलायन सम्बन्धी पुनर्वासन को लेकर मुख्यमंत्री योगी ने जिस दक्षता का परिचय दिया, वो उनके लिए राजनीतिक रूप से सबसे ज्यादा कारगर सिद्ध हुआ. फ्री राशन की व्यवस्था ने गरीब एवं हाशिए पर पड़े व्यक्ति में भी सरकार के प्रति विश्वास पैदा किया. स्वयं योगी ने इसे एक अवसर के तौर पर ग्रहण किया तथा अपनी सम्पूर्ण ऊर्जा लगभग 1 करोड़ प्रवासियों एवं 16 करोड़ गरीब लोगों के फ्री राशन की व्यवस्था करने में लगा दी. साथ हीं साथ गुंडे एवं असामाजिक तत्वों के खिलाफ

1: Corresponding Author

बुल्डोजर संस्कृति के सूत्रपात ने भी मतदाताओं को योगी एवं भाजपा के तरफ मुड़ने को बाध्य कर दिया.

सारिणी : 1 (उत्तर प्रदेश में 1989 से अभी तक हुए विधानसभा चुनाव के पश्चात दलगत स्थिति– सीटों संख्या एवं प्रतिशत)

वर्ष	कांग्रेस	भाजपा	लोकदल / जनता पार्टी / सपा	बसपा	अन्य) सीमान्त दल निर्दलीय नोटा आदि	कुल सीटें
1989	94 (27.9)	57 (11.6)	208 (29.9)	13 (9.4)	53 (21.2)	425
1991	46 (17.4)	221 (31.5)	34 (12.5)	12 (9.3)	112 (29.3)	425
1993	28 (15.15)	177 (33.3)	109 (17.9)	67 (11.1)	44 (22.55)	425
1996	29 (15)	175 (33.9)	109 (19.7)	67 (11.2)	45 (20.2)	425
2002	25 (8.9)	88 (20.7)	143 (25.4)	98 (23.2)	49 (21.8)	403
2007	22 (8.5)	50 (16.9)	97 (25.4)	206 (30.4)	28 (18.8)	403
2012	28 (11.65)	47 (15)	224 (29.13)	80 (25.91)	24 (17.31)	403
2017	7 (6.25)	312 (39.67)	47 (21.82)	19 (22.23)	18 (9.16)	403
2022	2 (2.33)	255 (41.29)	111 (32.06)	1 (12.88)	34 (11.44)	403

स्रोत : भारत का निर्वाचन आयोग , उ.ख : उतराखंड

सारिणी : 2 (2022 विधानसभा चुनाव में विभिन्न दलों की स्थिति)

पार्टी	कांग्रेस	भाजपा	सपा	बसपा	अपना दल (सोनेलाल)	सुभासपा	निषाद पार्टी	रालोद	सीमान्त दल	कुल
प्राप्त मत प्रतिशत	2.33	41.29	32.06	12.88	1.62	1.36	91.	2.85	4.7	100
दे गए सीट पर प्राप्त मत	2.36	44.15	37.25	12.88	40.76	29.77	36.48	33.88	--------	
सीटों पर विजय	2	255	111	1	12	6	6	8	2	403

स्रोत : भारत का निर्वाचन आयोग

2. मोदी की लोकप्रियता : कोरोना के द्वितीय लहर के दौरान मोदी की लोकप्रियता में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली थी. परन्तु बेहद व्यापक स्तर पर टीकाकरण कार्यक्रम ने पुनः मोदी को एक अटल स्थिति पर पहुंचा दिया, जहाँ चुनाव का मतलब सिर्फ और सिर्फ भाजपा की जीत हीं होती.

3. भाजपा की सांगठनिक दक्षता : कोई भी चुनाव बिना संगठन के सही तरीके से नहीं लड़ा जा सकता है. उत्साह और उमंग के द्वारा दो कदम तो जरूर बढ़ सकते हैं, परन्तु चुनाव जीतने के लिए स्पष्ट रणनीति का होना सबसे बड़ा कारक होता है. इस अर्थ में भाजपा विरोधी दलों के मुकाबले मीलों आगे खड़ी है. 24'7 भाजपा अपने रणनीति पर कार्य करती हुई दिखती है, वहीँ विपक्षी दल सिर्फ चुनाव के समय कमर कसते हुए नजर आए. लगभग सभी विपक्षी दलों के संगठन में दरार और आपसी अविश्वास साफ – साफ दिखा. सिर्फ कुछ हद तक समाजवादी पार्टी में हीं सांगठनिक एकजुटता दिख पाया. सड़कों पर सरकार की नीतियों के खिलाफ सिर्फ सपा के हीं समर्थक दिखे. बसपा का पूरा कैडर कहीं भी नजर नहीं आया. रही सही कसर स्वयं मायावती ने पूरी कर दी. अपने सबसे विश्वस्त सहयोगी लालजी वर्मा एवं रामअचल राजभर को चुनाव के पहले पार्टी से निष्काषित कर दिया तथा सुखदेव राजभर ने स्वास्थ्य कारणों से राजनीति से संन्यास की घोषणा कर दी. साथ हीं 'बहुजन मूवमेंट एवं सामाजिक न्याय' की विचारधारा को अपने मार्ग से भटका हुआ बताकर मायावती पर सीधा हमला भी बोल दिया.

4. महिला सुरक्षा : भाजपा के जीत में एक बड़ा कारण महिला सुरक्षा के मुद्दे पर भाजपा द्वारा अपनाए गए स्पष्ट नीति को भी जाता है. सीएसएसपी, कानपुर द्वारा किये गए पोस्ट पोल चुनाव अध्ययन में इस बात की तसदीक भी हो रही है.

सारणी : 3 (2022 विधानसभा चुनाव में पुरुष एवं महिला मतदान)

2022 चुनाव	भाजपा+	सपा+	बसपा	कांग्रेस	अन्य
पुरुष	52	37	8	1	2
महिला	57	34	7	1	1
उभयलिंगी	60	40	0	0	0

स्रोत : सीएसएसपी, कानपुर द्वारा आयोजित पोस्ट पोल सर्वे. सभी आंकड़े प्रतिशत में

केंद्र सरकार द्वारा लागू विभिन्न योजनाओं ने इसमें सबसे बड़ी भूमिका निभाई है. उज्ज्वला योजना, शौचालय योजना, राशन कार्ड योजना आदि ने महिलाओं में सम्मान का भाव पैदा किया. योगी ने भी महिला सम्मान पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाकर गुंडों में एक खौफ भी पैदा करने का काम किया. विशेष ध्यान देने वाली बात यह है कि बसपा एवं कांग्रेस की अगुवाई दो महिला नेत्री मायावती एवं प्रियंका गांधी कर रही थी. बावजूद इसके महिलाओं ने भाजपा पर जबरदस्त विश्वास जताकर सपा को हराने में प्रमुख भूमिका अदा की. दोनों दलों के मध्य महिलाओं द्वारा प्राप्त मत का अंतर 23 प्रतिशत रहा. शायद यह फैक्टर भाजपा के जीत और सपा के हार का प्रमुख कारण रहा .

5. राष्ट्रवाद की भावना का उभार : पिछले पांच छः वर्षों से भाजपा राष्ट्रवाद के मुद्दे पर मुखर तरीके से आगे बढ़ रही है.

हालांकि एक बड़ा वर्ग आज भी इनकी विचारधारा से सहमत नहीं है. परन्तु हिंदुत्व आधारित अस्सी और बीस की अपील ने मतदाताओं को जातिगत आग्रह छोड़कर एक दूसरे दृष्टिकोण से भी चुनाव को देखने के लिए विवश कर दिया. सम्बंधित सारणी इस बात की पुष्टि भी कर रहा है.

सारणी : 4 (विभिन्न जाति समूहों द्वारा किये गए मतदान का रूख)

	भाजपा+	सपा+	बसपा	कांग्रेस	अन्य
राजपूत (4%)	89	9	1	1	
ब्राह्मण (8%)	85	10	5		
वैश्य (4%)	66	27	7		
अन्य अगडी जातियां (3%)	79	14			7
जाट / गुर्जर (2%)	70	23	7		
यादव / अहीर (11%)	18	80	1		1
कुर्मी (6%)	86	10	2		2
कोयरी /मौर्य (6%)	72	20	6		2
राजभर (4%)	36	63			1
निषाद (3%)	43	14			43
अन्य पिछड़ी जातियां (9%)	70	22	4	3	1
जाटव (11%)	41	21	38		
पासी / धोबी) 6%)	63	29	6	1	1
अन्य अनुसूचित जातियां (2.7%)	77	11	11	1	
अशरफ़ मुसलमान (2.2%)	8	80	2	2	8
पसमांदा मुसलमान (17%)	16	82		1	1
अनुसूचित जनजाति (0.6%)	14	71	1		14
अन्य) 0.5%)	45	43	10		2
कुल–100 %					

स्रोतः सीएसएसपी, कानपूर द्वारा पोस्ट पोल सर्वे 2022. सभी आंकड़े प्रतिशत में.

अनुसूचित जाति, अनु. जनजाति एवं मुस्लिमों की जनसँख्या 2011 के अनुसार. शेष जातियों की जनसँख्या अनुमान के अनुसार

उपरोक्त आंकड़ों पर दृष्टि डालने से एक बात तो बिलकुल साफ हो जाती है कि सिर्फ यादव और मुस्लिम को छोड़कर सभी जातियों ने एकतरफा भाजपा को वोट दिया. दूसरे अर्थों में भाजपा ने पुनः जातियों के 'इन्द्रधनुषी गठबंधन' को जीवित कर एक बड़े वर्ग की रचना कर डाली है, जहाँ जातियों की अस्मिता और आकांक्षा की जगह वर्गीय हित की अवधारणा मजबूत नजर आने लगी है. उच्च वर्ग, पिछड़ी जातियों एवं दलितों के महासंसर्ग ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में पुनः एक ऐसा खांचा तैयार कर दिया है जिसे आने वाले समय में तोड़ना किसी भी विपक्षी पार्टी के लिए न सिर्फ दुष्कर होगा वरन अपने लिए वोट बेस तैयार करने में बड़ी मशक्कत करनी होगी. एक बात यहाँ पर और भी उल्लेखनीय है कि मुसलमानों का एक तबका बहुत तेजी से भाजपा की तरफ झुक रहा है. हालाँकि यह बात भी दीगर है कि भाजपा ने एक भी मुस्लिम को टिकट नहीं दिया. इससे यह सन्देश भी प्रकट हो रहा है कि मुसलमानों का हित उस व्यापक राष्ट्रवादी अवधारणा में ही निहित है जो एक विराट सनातनी हिन्दू राष्ट् में समाहित है. इसमें कोई आश्चर्य नहीं होगा जब आने वाले समय में मुस्लिम अपने आपको उस विराट सनातन राष्ट्र के स्वाभाविक अंग के तौर पर देखने लगें. 2024 का लोकसभा चुनाव इस दृष्टिकोण से बहुत हीं महत्वपूर्ण होने वाला है. पहले से हीं तीन तलाक के मुद्दे पर बड़ी संख्या में मुस्लिम महिलायें भाजपा से जुड़ चुकी हैं. शिया मुसलमान खुलकर भाजपा के साथ आ चुका है।

सामाजिक एवं बहुजन न्याय की अवधारणा पर आधारित राजनीति को सबसे बड़ा झटका लगा है. इसका कोर वोटर छिटककर भाजपा के पाले में जा चुका है. आंकड़े तो यही कह रहे हैं. बसपा के वोट बैंक में 9.5 प्रतिशत की एकमुश्त गिरावट ने कांशीराम के सपनों पर सबसे गहरा आघात किया है. मायावती के उटपटांग एवं आत्मघाती निर्णयों से पार्टी खत्म होने के कगार पर पहुँच चुकी है. दलित विमर्श एवं दलितों का आन्दोलन फिलहाल लम्बे समय के लिए ठन्डे बस्ते में चला गया है. दलितों में भी चुनाव पूर्व यह समझ बैठ गयी थी कि बहन जी चुनाव नहीं, बल्कि चुनाव लड़ने का नाटक कर रही हैं. इसलिए दूसरा ठिकाना ढूँढने में हीं भलाई है. कल तक जिस ब्राहमणवाद और छद्म राष्ट्रवाद के खिलाफ बहुजन समाज लामबंद था, आज वो उसी की देहरी पर बैठ गया है. इसीलिए 2022 का चुनाव एक अर्थ में युगांतकारी माना जा सकता है, जिसकी गूँज अभी लम्बे समय तक सुनाई देगी।

समाजवादी विचारधारा की जिस लड़ाई को मुलायम सिंह यादव ने सींचा था, जिसके आधार में जाति सबसे बड़े फैक्टर के तौर पर काम करता था, उसका पराभव भी इस चुनाव में होता हुआ दिख रहा है. हालांकि समाजवादी पार्टी ने अभी तक का अपना सबसे बेहतरीन प्रदर्शन किया और उसके वोट में 10 प्रतिशत से ज्यादा की बढ़ोतरी भी हुई. परन्तु फिर भी सरकार बनाने के जादुई आंकड़े से बहुत दूर रह गयी, क्योंकि भाजपा के वोट प्रतिशत में भी अप्रत्याशित रूप से लगभग 2 प्रतिशत की वृद्धि हो गई, जिसकी सम्भावना चुनाव प्रारम्भ होने तक बिलकुल नहीं दिख रही थी. जाहिर सी बात है कि भाजपा ने बसपा के वोट बैंक में जबरदस्त सेंधमारी कर दी. उल्लेखनीय है कि 2002 के पश्चात हुए सभी विधानसभा चुनाव में त्रिकोणीय संघर्ष हीं हुआ है, परेंतु 2022 का चुनाव पूरी तरह से द्विपक्षीय रहा. फलस्वरूप मतों के बंटवारे में सर्वाधिक मत प्राप्त करने वाले दल की सरकार बननी हीं थी. बसपा के मतों में गिरावट आएगी, इसका अंदाजा तो सभी को था, परन्तु इनका वोट भाजपा को ट्रांसफर हो जाएगा, इसकी

आश्वस्ति बिलकुल नहीं थी. वोटों में वृद्धि होने के बावजूद भाजपा के सीटों की संख्या में 57 की कमी हो गयी. लडे गए सीटों के आधार पर भाजपा को सपा से लगभग 7 प्रतिशत ज्यादा वोट मिला. और सारा गुणा–गणित इसी संख्या में छुपा हुआ है. भाजपा इस बात को बहुत हीं बेहतर तरीके से जानती थी कि इस बार की लड़ाई में 35 प्रतिशत वो बेंचमार्क है, जिसके नीचे जाने का मतलब सत्ता से हाथ धो बैठना है. इसलिए वो लगातार अपने वोट को लेकर सचेत थी. वहीँ दूसरी ओर अखिलेश यादव का चुनावी समर में प्रवेश बहुत देर से होता है. वो ड्राइंग रूम की राजनीति से आगे बढ़ हीं नहीं पा रहे थे. 3 अक्टूबर को लखीमपुर–खीरी में किसान हत्याकांड के बाद वे एवं सपा के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे. परन्तु फिर भी शुरूआती फोकस प्रियंका गाँधी पर ज्यादा था. लगा कि कांग्रेस का पुनर्जागरण हो रहा है. परन्तु कमजोर अथवा विलुप्त हुए संगठन के आधार पर कांग्रेस पर लोगों ने विश्वास नहीं जताया. फलस्वरूप समाजवादी पार्टी को बैठे बिठाए लोगों का साथ मिलना शुरू हुआ और तब जाकर सपा संघर्ष में वापस लौटती हुई नजर आई।

परन्तु ऐसा लगता है कि अखिलेश यादव अभी भी राजनीति के कच्चे खिलाडी हीं हैं. उन्होंने वो पिच चुनी जिस पर भाजपा बेहतरीन बैटिंग करती है. हिंदुत्व के पिच पर और राष्ट्रवाद के रनों के अम्बार का पीछा करना सपा के लिए कभी संभव नहीं था. बेहतर होता कि ये समाजवाद की पिच पर हीं बैटिंग करते. और तब मुद्दा हिंदत्व के बजाय महंगाई, बेरोजगारी, आरक्षण, किसान आन्दोलन, छुट्टा जानवर आदि बनते. पूरे चुनाव में भ्रष्टाचार का मुद्दा गायब रहा. स्वाभाविक हीं है इन मुद्दों के अभाव में मतदाता भ्रम की स्थिति में बने रहे और अंततः भाजपा को उनके पिछले पांच साल के कार्य पर वोट दे दिया. भाजपा द्वारा रखे गए स्पष्ट एजेंडे ने मतदाताओं के भ्रम को दूर करने का काम किया।

तरल कारण : उपरोक्त ठोस कारणों के अलावा कुछ ऐसे कारण भी थे जिसने अप्रत्यक्ष रूप से भाजपा को चुनाव जीतने में मदद की.

1. **आर.एस.एस की मदद** : संघ प्रमुख मोहन भागवत लगातार चुनाव पर नजर रखे हुए थे तथा समय समय पर हिंदुत्व एवं राष्ट्रवादी एजेंडे को लेकर बयान भी देते रहे. जिसका व्यापक प्रभाव जनमानस पर पड़ा.

2. **वोटों का ध्रुवीकरण** : चुनाव के प्रथम चरण से हीं मुस्लिम मतों में एकजुटता के कारण हिन्दू मतों में भी ध्रुवीकरण होने लगा. पश्चिम उत्तर प्रदेश के पहले चरण में यह उम्मीद जताई जा रही थी कि किसान आन्दोलन के कारण जाटों का वोट इस बार भाजपा के विरुद्ध जाएगा, परन्तु मुस्लिम मतों के ध्रुवीकरण के फलस्वरूप जाट मतों में भी 'प्रतिलोम ध्रुवीकरण' होने लगा. इसका सर्वाधिक फायदा भाजपा को हीं हुआ.

3. **फ्री राशन** : ज्यादातर विश्लेषक इस मुद्दे को भाजपा की जीत के पीछे सबसे बड़ा कारण बताते हैं. परन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि यह मुद्दा तात्कालिक तौर पर भाजपा के लिए संजीवनी का काम तो अवश्य किया परन्तु इसके पीछे शासन द्वारा गरीबों के हक में त्वरित गति से लिए गए निर्णय को जाता है. यह निम्न सारणी से भी स्पष्ट हो जाता है.

सारणी : 5 (गरीबों की सुविधाओं के लिए सबसे अच्छी सरकार)

कांग्रेस	ाजपा	सपा	बसपा	न्य	ोई भी नहीं
%2	%54	%29	%8	%4	%3

स्रोत : सीएसएसपी, कानपूर द्वारा पोस्ट पोल सर्वे, 2022.

4. **गऊ संरक्षण** : भाजपा लगातार गोवंश को लेकर बेहद संवेदनशील रही है. पूरे प्रदेश के सभी जिलों में गोवंश के संरक्षण हेतु गौशालाओं का निर्माण तथा इस सम्बन्ध में सामाजिक चेतना जगाने का भी काम सरकार द्वारा किया गया. जिससे हिन्दू मतों के ध्रुवीकरण में मदद मिली. आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति हेतु गोवंश के पांच तत्वों पर भाजपा द्वारा लगातार जोर दिया जा रहा है, जिसे मतदाताओं ने हाथो हाथ लिया और हिन्दू संस्कृति के प्रति अपने गौरव भाव को समझने का प्रयास किया.

5. **आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना** : प्रधानमंत्री मोदी विभिन्न माध्यमों से आत्मनिर्भर भारत की बात 2014 से कर रहे हैं. इस संकल्पना में भारतीय राष्ट्रीय गौरव एवं आत्मसम्मान, भारतीय संस्कृति और भारतीय कूटनीति तीनो समाहित है. जनता ने इसे अपने लिए एक कर्तव्यबोध की तरह लिया है. उन्हें विश्वास है कि मोदी हीं इस संकल्पना को पूरी कर सकते हैं.

6. **विपक्षी दलों में बिखराव** : सत्ता पक्ष के खिलाफ विपक्षी दलों में चुनाव पूर्व जो एकता होनी चाहिए, वो कहीं नहीं दिखी. भले गठबंधन हो या न हो, परन्तु कॉमन मुद्दों पर तो सहमति होनी हीं चाहिए. सरकार को घेरने का कोई मौका छोड़ना नहीं चाहिए. परन्तु इस बार का चुनाव इस अर्थ में भी विपक्षी दलों के लिए एक सबक दे गया. मायावती का राजनीतिक स्टैंड पूरी तरह से सपा और कांग्रेस के विरोध में था. स्वाभाविक हीं है कि ऐसी स्थिति में मतदाता के पास और कोई चारा नहीं बचा सिवाई भाजपा कके समर्थन हेतु।

और अंत में यही कहा जा सकता है कि 2022 का विधानसभा चुनाव भाजपा के लिए नई शक्ति और अवसर के रूप में रहा तो सपा के लिए खोये अवसर के रूप में. अगर अखिलेश यादव की दृष्टि स्पष्ट होती तो परिणाम कुछ और भी हो सकता था. परन्तु इन्होने अवसर ढूँढने के बजाय नकारात्मक वोटिंग को हीं अपना वोट बैंक मानते रहे. सच तो यही है कि सपा को सकारात्मक के मुकाबले नकारात्मक वोट ज्यादा मिले. भाजपा की पिच पर बैटिंग करते करते रहे और सत्ता का ख्वाब सजाते रहे।

REFERENCES

https://eci.gov.in/

http://ceouttarpradesh.nic.in/

http://csspindia.com/

https://lokniti.org/nes